भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 207

उत्तर देने की तारीख - 01/12/2025

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत डिजिटल कक्षा

†207. **श्री बिद्युत बरन महतो:**

श्री लुम्बाराम चौधरी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत डिजिटल कक्षा अवसंरचना और शिक्षक प्रशिक्षण की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान समग्र शिक्षा अभियान के तहत बजट आवंटन किया गया है और उसका इस्तेमाल किया गया है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस अभियान के अंतर्गत प्राप्त शिक्षण परिणामों को मापने के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): समग्र शिक्षा के तहत, कक्षा VI से XII तक के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को 1,76,728 स्मार्ट कक्षाओं को संस्वीकृति दी गई है।

वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक समग्र शिक्षा के तहत स्मार्ट क्लासरूम के लिए अनुमोदित परिव्यय और किए गए व्यय का विवरण इस प्रकार है: -

(रुपए लाख में)

वित्त वर्ष	**स्मार्ट क्लासरूम**	
	अनुमोदित परिव्यय	**किया गया व्यय**
2022-23	73823.20	66276.64
2023-24	53729.70	36947.14
2024-25	59518.80	11525.20

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की सिफारिशों के अनुरूप समग्र शिक्षा के तहत शिक्षक प्रशिक्षण/शिक्षा कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने का समर्थन है। समग्र शिक्षा के तहत किए गए प्रयास का उद्देश्य शिक्षक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) में भौतिक अवसंरचना को मजबूत करना; राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी) को इस प्रकार सहयोग प्रदान करना है कि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा, अनुसंधान तथा राज्य-विशिष्ट पाठ्यचर्या रूपरेखा का विकास स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ़ एसई) का प्रभावी और दक्षतापूर्वक अनुपालन कर सकें; जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) के पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण करना है तथा बीआरसी/सीआरसी आदि के माध्यम से विद्यालयों को सतत शैक्षणिक सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना के तहत राज्यों की विशिष्ट प्रस्तावों के अनुसार शिक्षकों, विद्यालय प्रमुखों, विषय शिक्षकों, संसाधन व्यक्तियों, प्रशिक्षकों, शिक्षा प्रशासकों, शिक्षक शिक्षकों, प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए सेवा-कालीन प्रशिक्षण तथा नोडल एजेंसियों के रूप में एससीईआरटी और डीआईईटी के माध्यम से प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में इनको शामिल करते हुए नव नियुक्त शिक्षकों के लिए अभिमुखीकरण प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

समग्र शिक्षा के तहत, डिजिटल शिक्षा हेतु शिक्षक क्षमता निर्माण को "ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल अवसंरचना" (दीक्षा) प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से समर्थन दिया जा रहा है, जो ई-सामग्री और डिजिटल शिक्षण संसाधन प्रदान करता है। विभाग ने दीक्षा पर "निष्ठा" (विद्यालय प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र उन्नयन हेतु राष्ट्रीय पहल) को एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में लागू किया है, जिसमें डिजिटल शिक्षण पद्धति, आईसीटी उपकरणों के उपयोग और प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षण मॉड्यूल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डीआईईटी, बीआरसी और सीआरसी शिक्षक की डिजिटल शिक्षा के लिए शिक्षकों की तैयारियों को सुदृढ़ करने हेतु संसाधन सामग्री, डिजिटल सामग्री, प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं का विकास करते हैं।

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से समग्र शिक्षा के तहत सभी कार्यकारी 613 डीआईईटी को चरणबद्ध तरीके से उत्कृष्ट केंद्रों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर, सरकार ने अब तक वित्तीय वर्ष 2023-24 में 125 डीआईईटी के उन्नयन हेतु 917.09 करोड़ रुपए तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 121 डीआईईटी के उन्नयन हेतु 1,512.50 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता संस्वीकृत की है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के अनुरूप, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने राष्ट्रीय शिक्षक व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी) पर एक दिशानिर्देश

दस्तावेज़ तथा राष्ट्रीय परामर्श मिशन (एनएमएम) पर एक ब्लूबुक जारी की है। एनपीएसटी विभिन्न चरणों/स्तरों पर शिक्षकों की दक्षताओं को परिभाषित करता है। एनएमएम पर ब्लूबुक में स्कूली शिक्षकों को उनकी क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने के लिए परामर्श हेतु विभिन्न प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

एनसीटीई ने एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) को अधिसूचित किया है, जो शिक्षा तथा कला, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा आदि जैसे किसी विशेष विषय में 4-वर्षीय एकीकृत द्वि-प्रमुख स्नातक डिग्री है। इसका उद्देश्य उत्साही, प्रेरित, योग्य, व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित और सुयोग्य शिक्षक तैयार करना है। आईटीईपी में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा (एनसीईटी) के माध्यम से किया जाता है।

(ग): भारत सरकार देशभर में अधिगम और शैक्षिक परिणामों को मापने के लिए आवधिक व्यापक पैमाने पर मूल्यांकन करती है। हाल ही में, दिनांक 4 दिसंबर 2024 को विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख, एनसीईआरटी द्वारा "परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण (पीआरएस) 2024" का आयोजन किया गया था जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत छात्रों में दक्षता के विकास के लिए मूलभूत, तैयारी और मध्य चरणों (क्रमशः कक्षा 3, 6 और 9 में आकलित) के अंत में उनके मूलभूत प्रदर्शन स्थिति को समझना था। यह सर्वेक्षण भारत में अधिगम परिणामों पर प्रणाली-स्तरीय परावर्तन के रूप में तैयार किया गया है, जो स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों में महत्वपूर्ण दक्षता, कौशल या अवसंरचनात्मक अंतराल को रेखांकित करता है। इस परख राष्ट्री सर्वेक्षण 2024 की राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की रिपोर्टें https://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en पर उपलब्ध हैं, जो आकलन के निष्कर्षों को प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया समर्पित डैशबोर्ड है।

****